मप्र में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

20 आईएएस के तबादले

भोपाल, 24 जुलाई. मध्यप्रदेश सरकार ने शुक्रवार देर रात को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 20 अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापनाओं के आदेश जारी किए हैं.

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1.	के.सी. गुप्ता	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार)	कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश
2.	सचिन सिन्हा	महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग
3.	राघवेन्द्र सिंह	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आनंद विभाग (अतिरिक्त प्रभार)	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आनंद विभाग (अतिरिक्त प्रभार)
4.	संदीप यादव	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रवासी भारतीय विभाग, (अतिरिक्त प्रभार)	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रवासी भारतीय विभाग, (अतिरिक्त प्रभार)
5.	जॉन किंग्सली	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा संचालक (पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग (अतिरिक्त प्रभार)	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग (अतिरिक्त प्रभार)
6.	डॉ. सुदाम खाड़े	आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर तथा आयुक्त (फील्ड), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर (अतिरिक्त प्रभार)	सचिव, मुख्यमंत्री
7.	भास्कर लक्षकार	आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (अतिरिक्त प्रभार)	आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर तथा आयुक्त (फील्ड), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर (अतिरिक्त प्रभार)
8.	अजय कटेसरिया	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा संचालक, कर्मचारी चयन मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार)	कलेक्टर, जिला रतलाम
9.	कुमार पुरुषोत्तम	प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश, भोपाल	अपर सचिव, मुख्यमंत्री एवं प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश, भोपाल
10.	रत्नाकर झा	अपर आयुक्त (राजस्व) उज्जैन संभाग, उज्जैन	कलेक्टर, जिला अनूपपुर
11.	केदार सिंह	कलेक्टर, जिला शहडोल	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोनिवि
12.	हर्षल पंचोली	कलेक्टर, जिला अनूपपुर	कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को), भोपाल
13.	अदिति गर्ग	कलेक्टर, जिला मंदसौर	वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश भोपाल तथा उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (अतिरिक्त प्रभार)
14.	प्रीति यादव	कलेक्टर, जिला आगरमालवा	कार्यकारी संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, इन्दौर
15.	मिशा सिंह	कलेक्टर, जिला रतलाम	कलेक्टर, जिला शहडोल
16.	गुरू प्रसाद	उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय	कलेक्टर, जिला खरगौन
17.	दिव्यांक सिंह	अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल	कलेक्टर, जिला मंदसौर
18.	डॉ. शेर सिंह मीना	आयुक्त, नगर पालिक निगम, सतना तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी, सतना (अतिरिक्त प्रभार)	कलेक्टर, जिला आगरमालवा
19.	सिद्धार्थ जैन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत इन्दौर	उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय
20.	हिमांशु प्रजापति	कार्यकारी संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, इन्दौर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, इन्दौर

अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई को औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। प्रमुख सचिव मनीष सिंह को ऊर्जा विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि प्रमुख सचिव डॉ.ई.रमेश कुमार को नर्मदा घाटी विकास विभाग सहित संबंधित संस्थाओं का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

एलपीजी सुरक्षा के लिए प्रशासन की नई पहल

विदिशा, घरेलू एलपीजी गैस के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने नई पहल की है. कलेक्टर कार्यालय (खाद्य शाखा) के निर्देश पर जिले में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम से जुड़े गैस वितरण वाहनों में एलपीजी सुरक्षा जागरूकता गीत भाई आया रे गैस सिलेंडर% का प्रसारण अनिवार्य किया गया है.जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि गैस वितरण के दौरान उपभोक्ताओं को सिलेंडर की सील और वजन की जांच, डिलीवरी के समय सुरक्षा मानकों का पालन तथा गैस रिसाव जैसी आपात स्थितियों में बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी इस गीत के माध्यम से दी जाएगी. यह गीत ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन द्वारा तैयार किया गया है.

जख्म देखे बिना ही बता दिया हालत गंभीर

जिला अस्पताल की इमरजेंसी व्यवस्था पर उठे सवाल

उपचार से पहले ही जिम्मेदारी से बचने की चर्चा

नवभारत न्यूज

विदिशा 24 जुलाई, जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी सेवाओं पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि इमरजेंसी वार्ड में तैनात कुछ चिकित्सक गंभीर रूप से घायल अथवा पीड़ित मरीजों की समुचित जांच किए बिना ही उन्हें मेडिकल कॉलेज या भोपाल रेफर कर देते हैं। इससे मरीजों और उनके परिजनों को तत्काल उपचार मिलने के बजाय दूसरे अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं. लंबे समय से लोगों के बीच यह चर्चा है कि जिला अस्पताल उपचार केंद्र के बजाय धीरे-धीरे रेफर सेंटर बनकर रह गया है.

शुक्रवार दोपहर ऐसा ही एक मामला सामने आया सड़क हादसे में घायल एक महिला को एक ऑटो चालक जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर पहुंचा. उस समय इमरजेंसी वार्ड में दो चिकित्सक मौजूद थे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चिकित्सकों ने महिला का प्राथमिक परीक्षण या घावों की विस्तार से जांच किए बिना ही उसकी हालत गंभीर बताते हुए मेडिकल कॉलेज भेजने की सलाह दे दी. बताया गया कि चिकित्सक ने कहा कि यदि यहां भर्ती भी कर लिया जाए तो बाद में मेडिकल कॉलेज ही रेफर करना पड़ेगा, इसलिए सीधे वहीं ले जाया जाए. इसके बाद ऑटो चालक घायल महिला को तत्काल मेडिकल कॉलेज लेकर रवाना हो गया. पूरी प्रक्रिया करीब दस मिनट में पूरी हो गई.

निष्पक्ष जांच की मांग

गंभीर दुर्घटनाओं, हृदय रोग, विषाक्तता या अन्य आपातकालीन मामलों में प्रत्येक मिनट महत्वपूर्ण होता है. ऐसे में प्राथमिक उपचार और आवश्यक जांच के बजाय सीधे रेफर किए जाने से मरीजों का कीमती समय नष्ट होता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का भी मानना है कि किसी भी मरीज को रेफर करने से पहले उसका प्राथमिक परीक्षण, जीवनरक्षक उपचार और आवश्यक चिकित्सकीय मूल्यांकन किया जाना चाहिए. रेफरल तभी किया जाना चाहिए जब संबंधित उपचार या विशेषज्ञ सुविधा अस्पताल में उपलब्ध न हो.जिला अस्पताल की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच आम नागरिकों ने स्वास्थ्य विभाग से इमरजेंसी सेवाओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की.

सिद्धचक्र महामंडल विधान

नवभारत न्यूज

बंडा 24 जुलाई. आर्यिका रतन दुर्लभमति माताजी के सानिध्य में सिद्धचक्र महामंडल विधान विश्व शांति महायज्ञ में श्रीजी की पूजन, अभिषेक, शांतिधारा, आरती हुई.

आर्यिका श्री ने कहा है कि सच्चा धर्म गुरुओं, साधु संतों की विनय वैयावृत्ति एवं अपने से बड़ों का सम्मान तथा माता-पिता की सेवा कैसे होती है. विश्व शांति की कामना कि भगवान से विधान किए जाते हैं. महापुरुषों ने सतियों ने धर्म ध्वजा फहराकर मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर लिया. अशोक पापेट ने बताया कि आर्यिका संघ का वर्षा योग का सौभाग्य मिला है. बाल ब्रह्म श्री नीलेश भैया कार्यक्रम का निर्देशन कर रहे. कार्यक्रम में विधायक वीरेंद्र सिंह, अशोक ठेकेदार, महेंद्र भूसा, संतोष चौधरी, विजय चौधरी, कमल बिलानी, डॉ पूर्णचंद्र, मुन्ना खटोरा, मुकेश कलारिया, राकेश डागीरहर, डॉ संजू, ब्रह्मचारी भैया-दीदी मौजूद थीं.

नीट परीक्षा मामले को लेकर प्रदर्शन

नवभारत न्यूज,टीकमगढ़। पलेरा/जतारा। नीट परीक्षा मामले को लेकर देशभर में विद्यार्थियों के बीच चल रहे विरोध के बीच टीकमगढ़ जिले के पलेरा एवं जतारा में छात्रों का आक्रोश देखने को मिला। नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं, परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्रों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया।

छात्रों ने पलेरा एवं जतारा नगर में विरोध रैली निकालकर अपनी आवाज बुलंद की और सरकार से परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की मांग की। छात्रों का विरोध प्रदर्शन शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल से शुरू हुआ। बड़ी संख्या में छात्र रैली के रूप में अंबेडकर चौराहे तक पहुंचे। रैली के दौरान छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग उठाई।

स्कूल से शुरू हुई छात्रों की रैली अंबेडकर चौराहे तक पहुंची। छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। छात्रों का कहना था कि यह प्रदर्शन विद्यार्थियों के भविष्य और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर किया गया है। ज्ञापन में छात्रों का कहना है कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगें रखने वाले छात्रों पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ हुई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

28 हजार हितग्राहियों को मिली पेंशन

गुना। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को पन्ना जिले से आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जून माह की पेंशन राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया। इस दौरान प्रदेश के 35 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों के खातों में 210 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी गई। इसी कड़ी में गुना जिले के 28,971 पेंशन हितग्राहियों के खातों में भी 1,73,82,600 रुपये (एक करोड़ तिहत्तर लाख बयासी हजार छह सौ रुपये) की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। इस राज्यस्तरीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष में देखा गया।

बहादुरपुर अस्पताल का उन्नयन

30 बिस्तरों का होगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

नवभारत न्यूज

मुंगावली। क्षेत्रीय विधायक बृजेंद्र सिंह यादव द्वारा क्षेत्र को एक ओर बड़ी सौगात दी है,जिससे इस सौगात से कई ग्राम पंचायतों का लाभ मिलेगा हमेशा से बहादुरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से शिकायतें मिलती थी कि वहां जगह अभाव के चलते इलाज कराने आने वाले मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था और इन्हीं समस्याओं को देखते हुए विधायक बृजेंद्र सिंह यादव ने सरकार से मांग की उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन कर दिया जिससे सरकार ने विधायक की बात को गंभीरता से लेते हुए बहादुरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का निर्णय लिया है।

11 करोड़ की राशि से मिलेगी नई दिशा

अब जब विधायक ने प्रयास से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन कर दिया गया तो जल्द ही इसका निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसमें सिविल निर्माण के साथ उपकरण और फर्नीचर की खरीदी की जाएगीद्य। साथ ही अस्पताल के उन्नयन होने से वहा सरकार द्वारा स्टाफ की भर्ती भी की जाएगी.

सारंगपुर में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित

राजगढ़ 24 जुलाई, का. जनपद पंचायत सारंगपुर के सभाकक्ष में ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर संचालन-संधारण एवं प्रबंधन नियम-2026 के संबंध में प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला आयोजित की गई. मध्यप्रदेश राजपत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 22 जून, 2026 को जारी नियमों के संबंध में आयोजित कार्यशाला में विकासखंड की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों (जीआरएस) ने भाग लिया. कार्यशाला दो चरणों में आयोजित की गई जिसको संबोधित करते हुए मुख्य कार्यपलन अधिकारी जनपद पंचायत हेमेन्द्र गोविल ने कहा कि ग्रामों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का सुचारु संचालन एवं संधारण ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है.

छपते-छपते

एनटीए ने 4 सीनियर जनरल मैनेजर और 16 यंग प्रोफेशनल्स की निकाली भर्ती

नई दिल्ली, 24जुलाई. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने परीक्षा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, विजिलेंस, फोरेंसिक और शैक्षणिक शोध जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए चार सीनियर जनरल मैनेजर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों पर तीन वर्ष के अनुबंध के आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी.

यह पहल प्रो. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली हाई-लेवल विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप की जा रही है. समिति ने परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक-सक्षम बनाने के लिए कई सुधार सुझाए थे.एनटीए ने पहली बार यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के जरिए 16 यंग प्रोफेशनल्स की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की है. इनकी सेवाएं परीक्षा संचालन, नीति निर्माण और तकनीकी सुधारों में ली जाएंगी. भर्ती किए जाने वाले जनरल मैनेजरों को परीक्षा केंद्र संचालन, देशभर में 500 से अधिक शहरों में फैले टेस्ट सेंटर नेटवर्क के प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक, निगरानी और परीक्षा संबंधी शोध एवं डेवलपमेंट की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. इसके अलावा आइटम बैंक, नॉर्मलाइजेशन, कंप्यूटर-एडैप्टिव टेस्टिंग और एआईआधारित असेसमेंट जैसे क्षेत्रों में भी काम करना होगा. साइबर सुरक्षा प्रमुख को एनटीए के सभी सिस्टम, नेटवर्क और डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी. साथ ही डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट-2023, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-2000 और CERT-In के दिशा-निर्देशों का पालन भी कराना होगा.इन पदों के लिए संबंधित विषय में उच्च शैक्षणिक योग्यता, 12 वर्ष तक का अनुभव तथा राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय टेस्टिंग संस्थानों में वरिष्ठ नेतृत्व का अनुभव अनिवार्य रखा गया है. साइबर सुरक्षा पद के लिए CISSP, CISM Øæ CISA जैसे प्रोफेशनल प्रमाणपत्र भी आवश्यक होंगे. NTA का मानना है कि इन नियुक्तियों से परीक्षा प्रणाली को अधिक विश्वसनीय, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी तथा भविष्य में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के संचालन में गुणवत्ता और जवाबदेही बढ़ेगी.

शिक्षा, पर्यटन, सांस्कृतिक विकास में अग्रणी होगा नरसिंहगढ़

नवभारत न्यूज

नरसिंहगढ़ 24 जुलाई, का. प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से कार्य कर रही है. नरसिंहगढ़ के साथ ही कुरावर सहित अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षा के लिये बेहतर प्रयास हो रहे है. नरसिंहगढ़ को पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास हो रहे है.नरसिंहगढ़ के पर्यटन व सांस्कृतिक विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

उपरोक्त बात प्रभारी मंत्री श्री चेतन्य कुमार काश्यप ने शुक्रवार को 42 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सांदीपनि विद्यालय के लोकार्पण समारोह में बोलते हुए कही. उन्होंने कहा कि प्रदेश के संतुलित एवं दूरदर्शी विकास के लिए शिक्षा, अधोसंरचना कनेक्टिविटी तथा सांस्कृतिक एवं पर्यटन विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

प्रभारी मंत्री ने कहा कि सांदीपनि विद्यालय में एलकेजी से कक्षा 12वीं तक लगभग 1300 विद्यार्थी अध्ययन करेंगे. श्री काश्यप ने कहा कि जिस प्रकार डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने शासकीय विद्यालय में अध्ययन कर कलेक्टर बने है उसी उसी प्रकार इस विद्यालय के विद्यार्थी भी भविष्य में उच्च पद प्राप्त कर नरसिंहगढ़ नगर तथा प्रदेश एवं देश का नाम रोशन करेंगे.

पटरी पार करते समय खौफनाक हादसा

घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा। राहगीरों की मदद से लहूलुहान और असहनीय दर्द से तड़प रही महिला को तत्काल गुना जिला अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के डॉक्टरों ने तुरंत प्राथमिक उपचार शुरू किया, लेकिन पैर की अत्यधिक गंभीर स्थिति और अत्यधिक खून बह जाने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज व सर्जरी के लिए भोपाल रेफर कर दिया है।

नवभारत न्यूज

गुना 24 जुलाई का। शुक्रवार की सुबह गुना शहर के जज्जी रेलवे ओवरब्रिज के पास उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब मायके जाने की जल्दी में एक बड़ा हादसा घटित हो गया। खड़ी मालगाड़ी के नीचे से पटरियां पार कर रही एक महिला अचानक ट्रेन के चालू हो जाने से उसकी चपेट में आ गई। ट्रेन के पहियों की जद में आने से महिला का दायां पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसे उपचार के दौरान काटने की जानकारी मिल रही है।

जानकारी के अनुसार, आरोन थाना क्षेत्र के ग्राम तमेड़ी निवासी पारी बाई पति खेमा बंजारा अपनी बहन अमरी बाई निवासी कुम्हारी, फतेहगढ़ के साथ अपने मायके जाने के लिए खुशी-खुशी घर से निकली थीं।

शुक्रवार सुबह लगभग 10:30 बजे दोनों बहनें आरोन बस स्टैंड पर उतरीं,रास्ते में जज्जी रेलवे ओवरब्रिज के नीचे मालगाड़ी खड़ी हुई थी। दोनों बहनों को दूसरी तरफ जाने की जल्दी थी। इसी आपाधापी में उन्होंने खड़ी मालगाड़ी के डिब्बों के नीचे से झुककर पटरी पार करने का जोखिम भरा कदम उठाया।

24 घंटे में पीएम मोदी के वीडियो को 30 करोड़ से ज्यादा व्यूज

नई दिल्ली, 24 जुलाई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरुवार देर रात जारी किए गए वीडियो संदेश को इंस्टाग्राम पर अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली है. पेपर लीक के मुद्दे और सरकार की प्रस्तावित कार्रवाई पर केंद्रित इस वीडियो ने महज 24 घंटे के भीतर 30 करोड़ से अधिक व्यूज हासिल कर एक नया रिकॉर्ड बनाया. वीडियो के वायरल होने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगभग 10 लाख नए फॉलोअर्स भी जुड़ गए. वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं और देशवासियों को संबोधित करते हुए पेपर लीक के मामलों पर सरकार का सख्त रुख दोहराया.

वीडियो को मिले प्यार पर भावुक हुए पीएम मोदी

नई दिल्ली, 24 जुलाई. नई दिल्ली, 24 जुलाई.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार रात 11:18 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक और वीडियो साझा कर देशवासियों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने हाल ही में पोस्ट किए गए अपने वीडियो को मिले सकारात्मक समर्थन और लोगों के स्नेह के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि जनता का यह प्यार उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है. वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कल रात आपसे जुड़ने का मुझे मौका मिला. थैंक्स टू एवरीबॉडी. यह आपका प्यार है, जो मुझे मिला है. आपसे जुड़ने का मौका मिला है.

बोले- आपका स्नेह और विश्वास हमेशा प्रेरित करता रहेगा

भरत तिवारी की मां से मिले सीएम सम्राट चौधरी

पटना, 24 जुलाई. भोजपुर जिले के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार सरकार ने शुक्रवार को तोड़ प्रशासनिक कार्रवाई की. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भरत तिवारी की मां आशा देवी और अन्य परिजनों की मुलाकात के कुछ ही देर बाद सरकार ने जगदीशपुर के एसडीओ संजीत कुमार को पद से हटा दिया. उन्हें अगले आदेश तक सामान्य प्रशासन विभाग, पटना में योगदान देने का निर्देश दिया गया है.इसके साथ ही एनकाउंटर के समय जगदीशपुर के एसडीपीओ रहे डीएसपी राजेश शर्मा को भी वापस पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है. भरत तिवारी के परिजनों ने डीएसपी राजेश शर्मा समेत अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है, जिसकी जांच जारी है.शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई मुलाकात में भरत तिवारी की मां आशा देवी ने बेटे की मौत को लेकर न्याय की मांग उठाई. परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने परिजनों को निष्पक्ष जांच और न्याय का भरोसा दिलाया.सरकार की ओर से की गई यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और मामले की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहा है. प्रशासनिक अधिकारियों पर हुई कार्रवाई को सरकार की शुरुआती जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.अब इस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं. सरकार का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा.

एसडीओ हटाए गए; डीएसपी को भी पुलिस मुख्यालय भेजा

सवाल | जनपद पंचायत में नियम ताक पर, उपस्थिति और योग्यता दोनों पर सवाल

उपस्थिति नहीं, फिर भी देख रहे पंचायत की महत्वपूर्ण शाखाओं के कार्य

आमला। जनपद पंचायत आमला में संविदा एवं अटैच कर्मचारियों की उपस्थिति व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार, संविदा ग्रेड-3 पर नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी बबन उमरे की उपस्थिति न तो कार्यालय के उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की जा रही है और न ही सार्थक एप पर। इसके बावजूद वे पंचायत की महत्वपूर्ण शाखाओं का कार्य देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनकी हाजिरी केवल अधिकारियों की जानकारी तक सीमित है। सूत्रों के अनुसार, यह मामला केवल एक कर्मचारी तक सीमित नहीं है। जनपद पंचायत में कई ऐसे करमचर एवं अटैच कर्मचारी हैं, जिनकी नियमित उपस्थिति का कोई अधिकृत रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पंचायत में 147 कर्मचारी सार्थक एप पर पंजीकृत हैं, लेकिन इनमें से केवल 123 कर्मचारियों की ही उपस्थिति दर्ज दिखाई देती है। ऐसे में शेष कर्मचारियों की उपस्थिति किस आधार पर दर्ज मानी जा रही है, यह बड़ा सवाल बन गया है। इससे कार्यालय की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं।

ट्रेजरी शाखा के प्रभारी की योग्यता पर भी सवाल : जनपद पंचायत की ट्रेजरी शाखा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि इस शाखा का कार्य देख रहे कर्मचारी इंदौरकर के पास न तो कंप्यूटर का आवश्यक डिप्लोमा है और न ही वित्तीय कार्यों के लिए अपेक्षित कंप्यूटर दक्षता। जबकि ट्रेजरी का पूरा कार्य अब कंप्यूटरीकृत प्रणाली से संचालित होता है। ऐसे में संबंधित कर्मचारी को इस महत्वपूर्ण शाखा की जिम्मेदारी दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं।नगर के युवा कानून सलाहकार जसवंत सिंह ठाकुर का कहना है कि जिस कर्मचारी के पास संबंधित कार्य की आवश्यक योग्यता नहीं हो, उसे अत्यंत महत्वपूर्ण वित्तीय शाखा का दायित्व सौंपना भविष्य में प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं का कारण बन सकता है।

उन्होंने उच्च अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर योग्य एवं प्रशिक्षित कर्मचारी की नियुक्ति सुनिश्चित करने की मांग की है।

रिकार्ड नहीं रखा गया, कहेंगे तो रजिस्टर बना लेगे

जब इस संबंध में जनपद पंचायत के सीईओ पंकज दारोटिया से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा संविदा कर्मचारी और अटैच कर्मचारियों का कोई अलग उपस्थिति रिकॉर्ड नहीं रखा गया है। आप कह रहे हैं तो रजिस्टर बना लेंगे। सीईओ का यह बयान भी कई सवाल खड़े करता है। यदि संविदा और अटैच कर्मचारियों का नियमित उपस्थिति रिकॉर्ड ही नहीं रखा जा रहा, तो उनकी कार्य अवधि, जवाबदेही और सरकारी नियमों का पालन किस आधार पर सुनिश्चित किया जा रहा है। यह विषय अब प्रशासनिक जांच की मांग कर रहा है।